



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 382] नई दिल्ली, सोमवार, नवम्बर 12, 1973/कार्तिक 21, 1895

No. 382] NEW DELHI, MONDAY, NOVEMBER 12, 1973/KARTIKA 21, 1895

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

## MINISTRY OF LABOUR

### ORDERS

New Delhi, the 12th November 1973

S.O. 691(E).—Whereas the Central Government is of opinion that an industrial dispute exists between the employers in relation to the management of J & K Minerals Limited, Jammu, and their workmen in respect of the matters specified in the Schedule hereto annexed;

And whereas the Central Government considers it desirable to refer the said dispute for adjudication;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 7A and clause (d) of sub-section (1) of section 10 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby constitutes an Industrial Tribunal of which Shri H. B. Sodhi, shall be the Presiding Officer, with headquarters at Chandigarh, and refers the said dispute for adjudication to the said Tribunal.

### SCHEDULE

Whether the workmen employed in the Coal Mines of J & K Minerals Limited, Jammu, are entitled to any House Rent Allowance? If so at what rates and from what dates?

[No. L-22011/13/73-LRII-(i)]

## श्रम मंत्रालय

## आदेश

नई दिल्ली, 12 नवम्बर, 1973

का०आ० 691 (प्र).—यतः केन्द्रीय सरकार की गयी है कि इससे उपाययुक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट विषयों के बारे में जे एण्ड के० मिनरल्स लिमिटेड, जम्मू के प्रबन्धन से सम्बन्धित नियोजकों और उनके कर्मचारियों के बीच एक औद्योगिक विवाद विद्यमान है ।

और यतः केन्द्रीय सरकार उक्त विवाद को न्यायनिर्णयन के लिए निर्देशित करना वांछनीय समझती है;

अतः, अब औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 7-क और धारा 10 की उपधारा (1) के खण्ड (घ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा एक औद्योगिक अधिकरण गठित करती है, जिसके पीठासीन अधिकारी श्री एच० बी० सोधी होंगे, जिनका मुख्यालय चण्डीगढ़ होगा और उक्त विवाद को उक्त औद्योगिक अधिकरण को न्यायनिर्णयन के लिए निर्देशित करती है ।

## अनुसूची

“क्या जे० एण्ड के० मिनरल्स लि० जम्मू की कोयला खानों में नियोजित कर्मकार किसी मकान किराया असे के हकदार हैं ? यदि हां, तो किन दरों पर और किन तारीखों से ?”

[सं० एल-22011/13/73-एल० आर० 2(i)]

S.O. 692(E).—Whereas by an order of the Government of India in the Ministry of Labour No. L-22011/13/73-LRII-(i), dated the 12th November, 1973, an industrial dispute between the employers in relation to the management of J & K Minerals Limited, Jammu, and their workmen employed at Jammu has been referred to the Industrial Tribunal, Chandigarh for adjudication;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (3) of section 10 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby prohibits the continuance of the strike in the said establishment.

[No. L-22011/13/73-(ii)]

T. S. SANKARAN, Jt. Secy.

का०आ० 692 (प्र).—यतः भारत सरकार के श्रम मंत्रालय के आदेश संख्या एल-22011/13/73-एल०आर०-2 (i), दिनांक 12 नवम्बर, 1973 द्वारा जे० एण्ड के० मिनरल्स लि०, जम्मू के प्रबन्ध से सम्बन्धित नियोजकों और उनके जम्मू में नियोजित कर्मचारियों के बीच विद्यमान औद्योगिक विवाद को न्यायनिर्णयन के लिए औद्योगिक अधिकरण, चण्डीगढ़ को निर्देशित किया गया है ।

अतः, अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 10 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार उक्त प्रतिष्ठान में विद्यमान हड़ताल के जारी रख जाने को एतद्द्वारा प्रतिषिद्ध करती है ।

[सं० एल-22011/13/73-एल० आर० 2(ii)]

टी० एस० शंकरन, संयुक्त सचिव ।